

18.41 hrs.

## PAPER LAID ON THE TABLE

## Notification under Customs Act, 1962

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY) : I beg to lay on the Table a copy of Notification No. 228-A/83-Customs (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 17th August, 1983 together with an explanatory Memorandum regarding exemption to stainless steel tubes for the manufacture of electrical heating elements from basic customs duty in excess of Sixty percent *ad valorem*, under Section 159 of the Customs Act, 1962. [Placed in Library. See No. LT-6882/83].

---

18.42 hrs.

## SUPPLEMENTARY DEMAND FOR GRANT (RAILWAYS, 1983-84)

—Contd.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय को यह अपील शुरू में ही कर देनी चाहिए थी, लेकिंव अब हम लोग जो बचे हुए हैं, उनके लिए वह अपील कर रहे हैं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें । अरब, 74 करोड़ 58 लाख रुपए की हैं। इन मांगों के जरिये अधिग्रहण, निर्माण, बदलाव आदि का काम किया जाना है या किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस रकम में से 95 करोड़ 53 लाख रुपये आठ रेलवे जान्ज में बांटे गए हैं और तीन रेल के कारखानों में यानी इंजिन तथा डिब्बे बनाने के कारखाने में और बाकी 79 करोड़ 5 लाख रुपया रेलवे बोर्ड के जिम्मे किया गया है। क्यों? इतनी बड़ी रकम इन सफेद हाथियों के लिए क्यों रखी गई है, इसका औचित्य बताना होगा। लगभग आधी रकम रेलवे बोर्ड के लिए रखी गई है। और कहते हैं कि पैसे की कमी है, यह मांग है, वह मांग है।

पहली बात मैं रेल मंत्री महोदय से यह

जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी राशि रेलवे बोर्ड के लिए किस काम के लिए रखी गई और क्यों रखी गई?

1975 से 1983 तक आज आठ साल हो गए, पटना में गंगा नदी पर रेलवे पुल बनाने की बात हो रही है। जांच हो रही है बार-बार यही जवाब मिलता है। हम फिर चिट्ठी लिखेंगे, उसका भी जवाब यही मिलेगा कि पूना में वाटर कमीशन जांच कर रहा है। श्री दंडवते भी इस दोष से बच नहीं सकते। वह भी यही जवाब देते थे। जो भी रेल मंत्री आता है, सब यही जवाब देते हैं कि जांच चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि यह जांच कब तक पूरी हो जाएगी? अगर आपके मन में पुल बनाने की बात नहीं है, तो बता दीजिए।

पाराशर जी ने ठीक ही कहा—गया और पटना को जोड़ने के लिए कब से मांग की जा रही है। वह एक धार्मिक स्थान भी है जो लोग विश्वास करते हैं—मैं तो विश्वास नहीं करता—पितृपक्ष में उन लोगों का एक मेला वहां लगता है। वहां बिना जल चढ़ाए हुए और बिना तर्पण किए हुए उनके पितरों को मोक्ष नहीं मिल सकता। लेकिन उस लाइन के लिए बाबा आदम के जमाने से मांग चली आ रही है कि इस लाइन को दोहरी कीजिए। यह जवाब कुछ दे देते हैं, आज तक यह काम नहीं हुआ। तो इसको करिए और नहीं करते हैं तब तक वहां डीजल से गाड़ी चलाइए।

इसी तरह आरा सासाराम लाइन की बात है। यह कहते हैं कि देश की तरकी होनी चाहिए। आरा-सासाराम लाइन का सर्वे हो चुका है, उसके बारे में भी आप बताने की कृपा करें। इसी तरह से फतुहा-इस्लामपुर लाइन है। आप 12-14 लाख रुपये देते हैं उसकी क्या जरूरत है? आप उसको ले लीजिए और उसको बड़ी लाइन में बदलकर चलाइये तो आपको आमदनी जरूर होगी।

आप बहुत से ओवर ब्रिज बनाने के निर्णय